

	कार्यवाही विवरण (जी.सी.एम.एस. नम्बर-2019/00666)	
23-12-2025	<p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। साक्ष्य वादी हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्य पेश नहीं करने से साक्ष्य वादी बन्द की गई। तदपश्चात विपक्षीगण ने साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर करते हुए पत्रावली में बहस सुने जाने का निवेदन किया। पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि मौजा सराडी पटवार मण्डल सराडी तहसील सलूमबर आराजी नम्बर 1701 रकबा 1.88 हैक्टेयर भूमि पर खातेदारान द्वारा अवैध बजरी के स्टोक कर उसे अन्यत्र ले जाया जा रहा है जिससे संपूर्ण कृषि भूमि बंजर हो गई है एवं मिट्टी का उपजाउपन समाप्त हो गया है। तथा वर्तमान में खातेदार नियमित रूप से उक्त भूमि में बजरी के स्टोक कर रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत विपक्षीगण के कृत्य को अवैधानिक करा खातेदारी अधिकार निरस्त करा बेदखली एवं भारी जुर्माने से दण्डित कराने का आदेश फरमावे।</p> <p>प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर विपक्षीगण ने जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया की उक्त प्रकरण में विपक्षीगण ने केवल मात्र बॉउण्ड्रीवॉल बनाने हेतु थोड़ी रेती लाया था। उसके अलावा न तो मैंने कभी कोई रेती का भण्डारण किया है न ही भविष्य में करूंगा। विपक्षीगण उक्त आराजीयात पर नियमित कृषि कार्य करते आ रहे हैं एवं इनके द्वारा न ही कभी बजरी का खनन किया गया है न ही कोई बजरी का स्टॉक किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि विपक्षी का जवाब रिकॉर्ड पर लेकर वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को निरस्त फरमाया जावे।</p> <p>प्रकरण में तहसीलदार सलूमबर से मौका रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट दिनांक 28-09-2022 एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 20.05.2025 अनुसार वादग्रस्त आराजीयात की भूमि पर किसी प्रकार का बजरी भण्डारण अथवा अकृषि कार्य नहीं होना पाया गया है।</p> <p>बहस मनन की गई। तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात मौका रिपोर्ट दिनांक 28-09-2022 एवं दिनांक 20.05.2025 का अवलोकन किया गया। वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात की भूमि पर किसी प्रकार का बजरी भण्डारण अथवा अकृषि कार्य नहीं होना पाया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा.का.अ. खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय दिनांक 23-12-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	




 (जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
 उपखण्ड अधिकारी,
 सहायक कलेक्टर सलूमबर
 जिला सलूमबर